अमेरिका में डीज़ल की कीमतें ज़ैलैंस्की के कारण बढ़ीं- ट्रंप

उन्होंने आरोप लगाया कि रुस की तेल रिफाइनरियों पर हमले ने विश्व ईंधन बाजार पर दबाव बढ़ाया

वॉशिंगटन, 14 सितंबर। अमेरिका में डीज़ल की कीमतों में तेज़ उछाल के बीच राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप का आरोप है कि रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन प्रतिष्ठानों पर यूक्रेन के लगातार हमलों के कारण वैश्विक ईंधन बाजार पर दबाव बढ़ रहा है।

- ट्रंप का मानना है कि मध्यपूर्व में जारी संघर्ष तथा अमेरिका -ईरान के बीच तनाव डीज़ल की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण नहीं है।
- अगर डीज़ल की कीमतें लम्बे समय तक ऊंची बनी रहीं तो इसका असर कृषि उत्पादन, खाद्य परिवहन और सप्लाई चेन पर पड़ेगा और यह अमेरिकी उपभोक्ता की जेब पर भारी पड़ेगा।

रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे (आरटी) के मुताबिक, अमेरिका में डीज़ल की राष्ट्रीय औसत कीमत इस सप्ताह पहली बार 6 डॉलर प्रति गैलन के पार पहुंच गई।

शुक्रवार को कीमत 6 डॉलर से अधिक दर्ज की गई, जबकि एक सप्ताह पहले यह करीब 5.85 डॉलर प्रति गैलन थी। पिछले साल इसी अवधि में डीज़ल की कीमत लगभग 3.71 डॉलर प्रति गैलन थी।

आयरलैंड की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के सामने डीज़ल की बढ़ ती कीमतों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यूक्रेनी नेतृत्व से रूस में डीज़ल उत्पादन से जुड़े ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की अपील की।

ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास रूस में हमला करने के लिए कई दूसरे लक्ष्य हैं, लेकिन डीज़ल ईंधन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात से भी इनकार किया कि डीज़ल की कीमतों में मौजूदा तेजी मुख्य रूप से मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण है। उन्होंने इसके बजाय रूस-यूक्रेन युद्ध और यूक्रेनी हमलों को कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बताया।

हालांकि, बाजार के जानकारों के मुताबिक, डीज़ल की कीमतों में हालिया उछाल के पीछे मध्य पूर्व में बढ़ ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी अहम कारण हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने भी अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। डीज़ल के निर्यात पर प्रतिबंध पहले लगाया गया था, जबकि बाद में इसे गैसोलीन उत्पादकों तक भी बढ़ ाया गया। डीज़ल निर्यात पर मौजूदा प्रतिबंध को सितंबर के अंत तक जारी रखने की बात कही गई है और इसके आगे बढ़ ने की संभावना भी जताई जा रही है।

अमेरिका में डीज़ल की कीमतों का असर सिर्फ परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कृषि मशीनरी, मालवाहक ट्रक और मालगाड़ियां बड़े पैमाने पर डीज़ल पर निर्भर हैं। इसलिए ईंधन की कीमत बढ़ ने का सीधा असर कृषि उत्पादन, खाद्य परिवहन और सप्लाई चेन की लागत पर पड़ सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की कुल लागत में ईंधन की हिस्सेदारी अलग-अलग क्षेत्रों और उत्पादों के अनुसार काफी भिन्न हो सकती है। ऐसे में अगर डीज़ल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो इसका असर अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है।

भारत नेपाल को 654 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा

नई दिल्ली, 14 सितंबर। केंद्र सरकार ने नेपाल को 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है। इसके तहत नेपाल विद्युत प्राधिकरण को कुल 654 मेगावाट तक बिजली आपूर्ति की जा सकेगी।

ऊर्जा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि 13 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक मुजफ्फरपुर-ढल्केबार 400 केवी डबल सर्किट लाइन के माध्यम से 600 मेगावाट और टनकपुर-महेन्द्रनगर 132 केवी सिंगल सर्किट लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक बिजली निर्यात की अनुमति दी गई है। जनवरी 2027 से निर्यात की जाने वाली बिजली की मात्रा की समीक्षा दिसंबर 2026 में की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार, हाल में आई बाढ़ से नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां घरेलू बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है और अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता पैदा हुई है। भारत की ओर से दी गई यह मंजूरी नेपाल की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

- नेपाल को 31 दिसम्बर 2026 तक रोज 18 घंटे बिजली सप्लाई की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तरुण तेजपाल ने गोवा में सरेंडर किया

अदालत द्वारा सरेंडर के लिये दी गई तीन सप्ताह की समय सीमा एक दिन बाद समाप्त हो रही थी

पणजी, 14 सितम्बर। मशहूर न्यूज मैगज़ीन "तहलका" के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने 2013 के एक रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सोमवार को गोवा की मापुसा अदालत में सरेंडर कर दिया।

- बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गत 6 अगस्त को तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई थी। तेजपाल ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लिस्ट होने से पहले सरेंडर करने से छूट मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 63 वर्षीय पूर्व संपादक को सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। उनके सरेंडर करने की तीन सप्ताह की यह समय सीमा कल समाप्त हो रही है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 6 अगस्त को तेजपाल को 2013 में अपनी एक पूर्व सहकर्मी के साथ रेप करने का दोषी ठहराया था और उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।

इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने 2021 में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को भी पलट दिया था। हालांकि तेजपाल लगातार यह दावा करते रहे हैं कि वे इस मामले में खुद एक पीड़ित हैं।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपनी अपील शीर्ष अदालत में लिस्ट होने से पहले सरेंडर करने से छूट की मांग की थी।

तेजपाल की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि शीर्ष अदालत के पास यह अधिकार है कि वह उचित मामलों में सरेंडर की अनिवार्यता से छूट दे सकती है और आरोपी के सरेंडर न करने की स्थिति में भी आपराधिक अपील को सूचीबद्ध कर सकती है।

वहीं, गोवा राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने दलील दी कि छूट के आवेदन पर मामले की मेरिट्स के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

जिला उपभोक्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुपरवाइजर को यह जानकारी दी। सुपरवाइजर ने उससे कहा कि वाहन की व्हील बैलेंसिंग करवाने पर यह समस्या खत्म हो जाएगी। ८

एक अक्टूबर 2018 को दूदू के पास उसकी कार सड़क के बीच पड़े सांड से टकरा गई, लेकिन उसके आगे के एयरबैग नहीं खुले।

वर्ष 2020 के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तमाम निकायों में जाकर रोड शो करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, उसका पूरा असर निकाय चुनावों में जनादेश के तौर पर स्पष्ट दिखाई दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले निकाय चुनाव में जहां 50 प्रतिशत नगर निगमों में भाजपा का बोर्ड था, वहीं इस बार 60 प्रतिशत बोर्ड भाजपा अपने स्तर पर तथा 80 से 90 प्रतिशत बोर्ड निर्दलीयों के समर्थन के साथ बनाने की स्थिति में है। इसके अलावा, 27 प्रतिशत नगर परिषदों से आगे बढ़ते हुए भाजपा इस बार 42 प्रतिशत बोर्ड अपने स्तर पर तथा 83 प्रतिशत निर्दलीयों के समर्थन के साथ बनाने की स्थिति में है।

इसी प्रकार, गत निकाय चुनाव में काबिज 31 प्रतिशत नगरपालिकाओं की तुलना में इस बार 60 प्रतिशत से अधिक बोर्ड भाजपा अपने स्तर पर बनाने जा रही है।

अगर राजधानी की बात करें तो जयपुर नगर निगम की स्थापना से अब तक लगातार 7वीं बार भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में जयपुर के टुकड़े करके 2 नगर निगम बनाने के निर्णय को भी जनता ने पूर्ण रूप से नकारा है। इस बार निकाय चुनाव में मात्र 63.55 प्रतिशत की वोटिंग होने के बावजूद, भाजपा एकतरफा बहुमत के साथ जयपुर नगर निगम में बोर्ड बनाएगी। जहाँ पिछली बार जयपुर संभाग में 17 प्रतिशत तथा भरतपुर संभाग में केवल 6 प्रतिशत निकायों में भाजपा का बोर्ड था, वहीं, इस बार जयपुर एवं भरतपुर दोनों संभागों में 60 प्रतिशत से अधिक निकायों में भाजपा बोर्ड बनाने जा रही है। इसी प्रकार 6 जिलों -बूंदी, दौसा, हनुमानगढ़, करौली, धौलपुर और भरतपुर में किसी भी निकाय में पिछली बार भाजपा का कोई बोर्ड नहीं था। लेकिन इस बार दौसा में 7, भरतपुर में 6, बूंदी में 5, हनुमानगढ़ में 5, करौली में 4 और धौलपुर में 2 निकायों में भाजपा बोर्ड बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि राजस्थान में शहरी क्षेत्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और राजस्थान सरकार के सुशासन पर मुहर लगाते हुए डबल इंजन में ट्रिपल इंजन भी जोड़ दिया है। 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के तहत, राजस्थान के सभी 309 निकायों में भाजपा को पिछली बार से दोगुने से अधिक निकायों में जनादेश मिला है।

तृणमूल से एनसीपीआई में गये 20 सांसदों में से 17 भाजपा में जायेंगे ?

मुर्शिदाबाद, बहरामपुर व जंगीपुर से सांसद सीधे भाजपा में नहीं जाना चाहते, वे राजग में बने रहेंगे

कोलकाता, 14 सितंबर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से अलग होकर नैशनलिस्ट सिटिज़ंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए 20 लोकसभा सांसदों में से 17 अगले महीने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं। कूचबिहार से लोकसभा सांसद और एनसीपीआई सांसदों के खेमे के प्रमुख नेताओं में शामिल जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने सोमवार को यह दावा किया।

- वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तृणमूल के 20 सांसदों ने एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया था। उन्हें एनसीपीआई लोकसभा सदस्य के रुप में मान्यता देने का मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लम्बित है।

बसुनिया ने कहा कि मुर्शिदाबाद से अबू ताहेर खान, बहरामपुर से यूसुफ पठान और जंगीपुर से खलीलुर रहमान सीधे भाजपा में शामिल नहीं होना चाहते। हालांकि, ये तीनों सांसद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ बने रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि शेष 17 सांसद दुर्गा पूजा से पहले या उसके तुरंत बाद एनसीपीआई छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। बसुनिया के मुताबिक, दो-तिहाई सांसदों के किसी दल में विलय के लिए 14 सांसदों की जरूरत होती है, जबकि उनके खेमे में 17 सांसद हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दल-बदल कानून लागू नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उसके 20 लोकसभा सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया गया है। यह बात भी कही गई है कि ये सांसद राजग का भी हिस्सा बन सकते हैं। इन 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्हें एनसीपीआई के लोकसभा सदस्यों के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। हालांकि, अभी तक लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इस संबंध में कोई मान्यता नहीं दी गई है।

जाने-माने एआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एआई के रैगुलेशन की उनकी मांगों ने एआई कंपनियों में निवेश करने वालों की सोच पर भी असर डाला है। ऐसी खबरें हैं कि एआई कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन में तेज गिरावट आई है। सैकेंडरी मार्केट के निवेशक अब सोच रहे हैं कि यदि उद्योग के नेता खुद एआई कंपनियों और उनके भविष्य के मुख्य कार्यक्रमों को नियंत्रित करने की मांग कर रहे हैं, तो इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा।

अधिकांश बड़ी एआई कंपनियों के शेयरों के मूल्य में तेज गिरावट आई है और बाजार में एआई को लेकर पहले जो उत्साह था, वह अब कम होता दिख रहा है।

पहले जहाँ एआई कंपनियों के शेयरों की कीमतें तेजी से आसमान छू रही थीं, वहीं अब उनमें तेजी से गिरावट आ रही है। नए निवेशक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे और इसलिए भविष्य के निवेश और ग्रोथ के लिए मिलने वाली पूंजी भी कम हो जाएगी।

हालांकि एआई को लेकर जो डर है, उसके बावजूद राजनेता, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, बेफिक्र हैं। वे नहीं चाहते कि अमेरिकी एआई उद्योग की रफ्तार थोड़ी भी धीमी हो, क्योंकि इससे अमेरिका के सबसे बड़े एआई प्रतिद्वंद्वी चीन के एआई उद्योग को आगे बढ़ने और मजबूत स्थिति में आने का मौका मिल सकता है।

इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है और ट्रंप इसमें किसी तरह का समझौता नहीं चाहते। अमेरिकी उद्योग को सबसे आगे रहना चाहिए और चीन को अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने नहीं दिया जा सकता। इसलिए ट्रम्प इस उद्योग के नेताओं की चिंताओं को महज डर फैलाने की कोशिश बता रहे हैं।

ट्रंप चाहते है कि अमेरिकी एआई अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़े। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी एआई को सबसे आगे रहना चाहिए और चीन को अमेरिका से आगे निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करना एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में हार मानने जैसा होगा, जो नए औद्योगिक युग की शुरुआत है। उनका मानना है कि अमेरिका इस नई औद्योगिक क्रांति में चीन से एआई की जंग नहीं हार सकता और न इस नए औद्योगिक युग में हार मान सकता है।

'जंगलों में से निजी भूमि, बाहर निकालने की व्यवस्था करें'

शिमला, 14 सितंबर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जंगलों के भीतर मौजूद निजी जमीन के साथ-साथ धीरे-धीरे वन भूमि को भी इस्तेमाल में लिए जाने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर एक व्यापक नीति की जरूरत है। अदालत का कहना है कि जंगलों के भीतर निजी जमीन का इस्तेमाल बढ़ ने से वन भूमि के रखरखाव और प्रबंधन पर असर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यह केवल हिमाचल प्रदेश से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की समस्या है।

- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे राष्ट्रीय स्तर की समस्या बताया

जंगलों में आग की घटनाओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि प्रदेश में वन भूमि के भीतर निजी भूमि के कुछ हिस्से मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि इन निजी जमीनों के मालिक धीरे-धीरे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

जयपुर, कोटा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जयपुर तथा नगरपालिका सुकेत के कुछ बूथों के परिणाम ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इन नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम पूर्ण रूप से घोषित नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव निर्धारित तिथियों पर कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चारों निकायों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिये हैं। इनके लिए अलग से तिथियां जारी की जाएंगी।

'झूठ की गूंज के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साबित कर दिया है कि प्रदेशवासियों का डबल इंजन सरकार के सुशासन और विकास नीतियों को पूरा समर्थन प्राप्त है।" पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि इस परिणाम से राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और जन-जन के जीवन में खुशहाली लाने का सरकार का संकल्प और अधिक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने सभी विजयी प्रत्याशियों के साथ-साथ, पार्टी के निष्ठावान और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी।

सालियान केस में सी.बी.आई. की एफ.आई.आर में उद्धव व आदित्य ठाकरे का भी नाम

हाईकोर्ट के निर्देश पर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर की मौत के मामले में सी.बी.आई. ने जांच शुरु की

मुंबई, 14 सितंबर। बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। एफआईआर में शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे और अभिनेता डीनो मोरिया समेत 33 से अधिक लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

- एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे के अलावा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सहित 33 लोगों के नाम हैं
- दिशा सालियान की मौत मलाड में एक इमारत से गिरने से हुई थी। पुलिस ने जांच करके अदालत में कलोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। दिशा के पिता की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को जांच के लिये सौंपा था।

सीबीआई के अनुसार, एफआईआर में हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश, साक्ष्य नष्ट करने और आरोपियों को कथित तौर पर बचाने के लिए गलत जानकारी फैलाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच की जा रही है।

जांच का दायरा दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों के साथ-साथ मामले को कथित तौर पर दबाने और जांच को प्रभावित करने से जुड़े पहलुओं तक रखा गया है। सीबीआई यह भी जांच करेगी कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी ने सरकारी संसाधनों, पुलिस मशीनरी, दस्तावेजों अथवा आधिकारिक रिकॉर्ड का कथित तौर पर दुरुपयोग किया था। रिकॉर्ड से छेड़छाड़, दस्तावेजों को नष्ट करने या दबाने तथा जांच को प्रभावित करने के आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी।

सीबीआई की जांच के दायरे में आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के अंगरक्षक, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाझे, परमबीर सिंह, पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत अन्य लोगों की भूमिका भी शामिल बताई गई है। सीबीआई की एफआईआर में दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में कथित देरी से जुड़े डॉक्टरों और कर्मचारियों के अलावा डॉ. संजय जाधव तथा कलिना स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के संबंधित अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मालाड स्थित इमारत से गिरने के बाद दिशा सालियान की मौत हुई थी। इसके बाद मालवणी पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। दिशा सालियान के पिता ने बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

पाकिस्तान ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाकिस्तानी रुपये कर दी है।

इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने नवीनतम सबसे वांछित आतंकवादियों की रेड लिस्ट में भगोड़ा घोषित किया है। हालांकि, पाकिस्तान की इस चाल को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने और अपनी सरजमीं पर पल रहे आतंकी आकाओं को छिपाने की सोची-समझी साजिश माना जा रहा है।

पाकिस्तान ने 2021 में दावा किया था कि अजहर अब देश में नहीं है और अफगानिस्तान भाग गया है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार तब से यही कहती आ रही है कि जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख पाकिस्तानी धरती पर नहीं है।

पंजाब के मु.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

द्विपक्षीय खेल मुकाबले की अनुमति नहीं देती, जिसके खिलाफ भारत ने पिछले साल ही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद थोड़े समय का सैन्य अभियान चलाया था। इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।

लेकिन ओलंपिक चार्टर का पालन करते हुए, खेल मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में एक-दूसरे के खिलाफ खेल सकते हैं और ऐसे आयोजनों के लिए भारत सीमा पार से आने वाले खिलाड़ियों को यहां खेलने से नहीं रोकेगा।

इसके बावजूद, पाकिस्तान ने पिछले साल तमिलनाडु में हुए जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच के जबरदस्त तनाव को इसका कारण बताया था।

मान ने कहा कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लीग चरण के मैच जालंधर में खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली स्टेडियम में होंगे।

प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाते हुए मान ने कहा कि पंजाब, राज्य के इतिहास में पहली बार होने वाले इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

"हॉकी इंडिया" के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हॉकी महासंघों के बीच संबंध "बहुत अच्छे" हैं।

सिंह ने कहा, "मैं यह बात रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के हॉकी महासंघों के बीच हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।"

उन्होंने कहा, "आपने जरूर देखा होगा कि जब भी मैं जाता हूं और भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा देती है, तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी टीम से मिलता हूं। वहां के खिलाड़ी भी बहुत सम्मान दिखाते हैं।"

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 27 अक्टूबर को जालंधर में होगी और फाइनल मुकाबला 5 नवंबर को मोहाली में खेला जाएगा।

'एक देश पर निर्भरता को छोड़कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चेतावनी दी कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने से साझा आर्थिक प्रगति में बाधा आ सकती है। उन्होंने टैक्नॉलजी तक सभी की समान पहुंच की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत ने पहले ही सीमित और कुछ ही देशों पर निर्भर आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरी का अनुभव किया है। 2020 में भारत-चीन सीमा पर संघर्ष के बाद चीनी सप्लाई और क्लियरैंस में कुछ बाधा आई थी। 2025 में अमेरिका के साथ व्यापारिक टकराव के दौरान, चीन द्वारा दुर्लभ-पृथ्वी मैग्नेटर के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर भारत के ऑटोमोबाइल उत्पादन पर पड़ा था

इसलिए शी की पेशकश और मोदी की चेतावनी के बीच का अंतर ब्रिक्स के भीतर के एक मुख्य तनाव को उजागर करता है। चीन ग्लोबल साउथ में अपने तकनीकी प्रभाव का विस्तार करना चाहता है, जबकि भारत पश्चिमी देशों पर निर्भरता को खत्म करके चीन पर निर्भरता को नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि ब्रिक्स के भीतर सहयोग चाहता है।

विश्लेषकों का कहना है कि ब्रिक्स के विस्तार के साथ इस तरह के मतभेद स्वाभाविक हैं, क्योंकि इसमें अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं, भू-राजनीतिक संबंधों, आर्थिक हितों और वाशिंगटन के साथ अलग-अलग रिश्ते रखने वाले देश शामिल हैं। चीन और भारत के बीच अविश्वास शायद इस समूह की सबसे बड़ी आंतरिक कमज़ोरी है। फिर भी जरूरी नहीं कि ये तनाव जरूरी नहीं कि सहयोग में बाधा बनें। इसके बजाय, ब्रिक्स अब आम सहमति और मतभेदों के मेल के साथ काम कर रहा है।

इसके बावजूद, शिखर सम्मेलन में काफी हद तक आम सहमति देखने को मिली। सदस्यों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया, जिसमें एकतरफा फैसलों, संरक्षणवाद और जबरदस्ती थोपे जाने वाले आर्थिक कदमों का विरोध किया गया। अमेरिका के टैरिफ, प्रतिबंध और डॉलर को चुनौती देने वाले देशों के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों ने एकजुटता के लिए एक अहम बाहरी वजह का काम किया।

"डी-डॉलराइज़ेशन (डॉलर पर निर्भरता कम करना) सहयोग का एक और क्षेत्र था। ब्रिक्स देशों ने व्यापार को आसान बनाने और अमेरिकी वित्तीय दबाव के प्रति अपनी कमज़ोरी कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं के अधिक इस्तेमाल और आपस में जुड़े पेमैंट सिस्टम के ज्यादा इस्तेमाल का समर्थन किया। हालांकि, इस बात पर अब भी सहमति नहीं है कि समूह को डॉलर से कितनी तेजी से और किस हद तक दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ सदस्य देशों के आर्थिक और राजनीतिक संबंध अलग-अलग हैं।

इसलिए भारत के लिए यह सम्मेलन रणनीतिक संतुलन बनाने की एक कवायद था। नई दिल्ली ने ब्रिक्स की एकता बनाए रखने, चीन और रूस के साथ संबंधों को गहरा करने और ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की कोशिश की, साथ ही अमेरिका और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी तरह के टकराव से बचने का प्रयास किया।

इस सम्मेलन का व्यापक महत्व उभरती हुई टैक्नॉलजी, फायनैंस और ग्लोबल ट्रेड को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रभावित करने की ब्रिक्स की बढ़ती महत्वाकांक्षा में निहित है। चीन का तर्क है कि ग्लोबल साउथ को इन नियमों को बनाने में बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, क्योंकि यह विशाल बाजारों और बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ग्लोबल गवर्नैंस के एक वैकल्पिक केन्द्र के रूप में ब्रिक्स की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके सदस्य देश अपने आपसी मतभेदों और प्रतिद्वंद्विता को संभाल पाते हैं या नहीं।

नई दिल्ली सम्मेलन ने दिखाया कि ब्रिक्स अधिक महत्वपूर्ण तो बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि अधिक एकजुट भी हो रहा हो। इसकी ताकत उसके सामूहिक प्रभाव में है, जबकि इसकी कमज़ोरी इसी सामूहिक शक्ति के भीतर मौजूद परस्पर विरोधी हितों में है।

'75 जिलों के लिए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी और कांग्रेस ने अपने-अपने अलग घोषणापत्र जारी किए। कांग्रेस का घोषणापत्र, जिसे "न्याय पत्र" कहा गया, 5 अप्रैल 2024 को जारी हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र इसके कुछ समय बाद 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया।

लेकिन लगभग हर चुनाव में घोषणापत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गठबंधन के कारण पार्टी का राज्यव्यापी घोषणापत्र अक्सर लोगों की नज़र में नहीं आ पाता था। सहयोगी दल अलग-अलग पार्टी दस्तावेजों के आधार पर प्रचार करते थे, हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ दोनों दलों के मुद्दे काफी हद तक समान थे। फिर भी कई मुद्दों पर उनके खास वादे अलग-अलग थे। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया था, जिसका कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लेख नहीं था। इस बार अखिलेश यादव इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि घोषणापत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया वास्तव में चुनाव में असरदार साबित हो।

करीब दो महीने पहले जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ हुई एक रणनीतिक बैठक में अखिलेश यादव ने यह विचार रखा था। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा था कि पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्रों के सामने मौजूद चुनौतियां एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था, अतीत में पूरे यूपी के लिए एक साझा व्यापक घोषणापत्र अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की खास मांगों को पूरा नहीं कर पाता था। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने इसे लागू करने के निर्देश जारी किए।

समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के नेताओं से कहा गया है कि वे हर जिले की आकांक्षाओं और चुनौतियों की एक विस्तृत सूची तैयार करें। उन्हें पांच प्रमुख समस्याओं, ऐसी परियोजनाओं जो लंबे समय से बंद या उपेक्षित पड़ी हैं, और जमीनी स्तर पर पहले से मौजूद रोजगार के अवसरों की सूची तैयार करनी होगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908